







# बाघमारा-निरसा-झरिया

## गजलीटांड खान हादसे की बरसी पर समा, शहीद मजदूरों को दी श्रद्धांजलि

शुभम संदेश। कतरास

शुक्रवार को गजलीटांड खान हादसे की बरसी के मौके पर शहीद स्मारक स्थान पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बीमोंसील के अधिकारी, शिवायक, राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों के नेता मौजूद थे। सभी ने शहीद कालोंमें को याद करते हुए उप अधिकारियों को याद करते हुए उप अधिकारियों को याद करते हुए, जिसमें कैफान शरीफ और गोता पाठ हुआ। माहोल पूरी तरह से श्रद्धा और भावुकता से भरा रहा। सभी ने दो मिनट का मान रखवाल शहीदों की आत्मा की जांति के लिए प्रार्थना की। बीमोंसील के सीएमडी मंत्री अवाल ने मौके पर मौजूद मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की और कहा कि आप अंजान को कोई बाकाया बाकी है, तो कैफान के नियम के तहत उसे जरूर दिया जाएगा। साथ ही अगर किसी को



### हादसा कैसे हुआ था ?

25 सितंबर 1995 को रोट, गजलीटांड कोलियारी की छह नव खदान में कारोनी नदी का पानी पुस गया था, जिससे अंदर काम कर रहे 64 मजदूरों की मौत हो गई। वे सभी को जमानामधी भूमि मिली थी। अज भी यह घटना कोलियार की सबसे बड़ी खदान दुर्घटनाओं में गिनी जाती है। ब्रह्मदेवनामों से सीएमडी मंत्री अग्रवाल, ट्रेड यूनियक मधुसुप्रसाद महतो, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, निदेशक संजय सिंह, भक्तपा माले नेता हल्कत महतो, जामुनों के जगद्दन प्राप्त राज, शिव प्रसाद महतो, पूर्ण मुखिया सुरेश महतो, भाजपा नेता मंशु पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रामीण अमित राजवर, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, सुषीत महतो, कुंज सिंह, श्रीकृति सिंह, अमृत सिंह आदि मौजूद थे।

### न्यूज अपडेट

#### अवैध देशी शराब के साथ संचालक गिरफतार

कुमारधबी (शुभम संदेश)। कुमारधबी वाजर में अवैध देशी शराब की बिक्री की लोगों द्वारा की गयी शिकायत पर कुमारधबी पुलिस ने सब्जी पट्टी में गूँगवार को रात छापमारी की। अवैध देशी शराब की बालों के साथ प्रैम साव का विप्रवार वह पुलिस से उल्लंघन गया और नॉक-इंटॉक कर ली। उसे जेल भेजने की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों शान्ति समिति की बैठक में कुमारधबी क्षेत्र के आठ-नौ दोंबों में अवैध देशी शराब की खुलेआम बिक्री का मामला उठाया गया था। कहा गया कि जीटी रोड के किनारे मैथन मोड़, शंकर टाकोज के पास, पोटारी मोड़ के पास, पालुलर नासिंग हाम के पास दौरान वह पुलिस से उल्लंघन गया और नॉक-इंटॉक कर ली। उसे जामाना भारतीय वाकाये होती रहती है। लोग काफी परेशान हैं, इससे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। लोगों की शिकायत पर पुलिस इंस्पेक्टर फाय होरो ने कर्तव्याकारी का भरोसा दिलाया था। उहोंने कहा कि नशा के खिलाफ आगे भी अभियान चलाया जायेगा।

#### मारवाड़ी महिला समिति का गरबा-डांडिया नाइट



चिरकुंडा (शुभम संदेश)। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति, चिरकुंडा शाश्वत गुरु शुक्रवार की संचाया के बायालीय में गरबा एवं डांडिया नाइट का रात्रा आयोजन किया गया। इस आयोजन के मारवाड़ी समाज के दर्जों में शामिल हुए। एवं अंकुश लगानी और अंजु सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिनिधि जितेश रजवर, विधायक प्रतिनिधि सुनी श्रीवास्तव, एवं ग्रा.

शंकर अमित, सचिवाद सिंह, मंत्री अमुज सिन्हा, शंकर चौहान, परजें इक्वाल, एपा बोंडी, रामवत पासवान, जिप प्रतिन







मंथन

## संवेदनाओं से सशक्त होगी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था

जारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गण्य की स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 160 चिकित्सकों को नियुक्त पत्र सौंपा है। इनमें सहायक प्राध्यार्थक और विशेषज्ञ पदाधिकारी शामिल हैं। यह बल के बल नियुक्तियों का आपचारिक आयोग नहीं, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार है। स्वास्थ्य सेवा का मूल उद्देश्य केवल इलाज तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें संवेदनाओं और सेवा-भाव का गहरा संबंध होता है। मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने सही ही कहा कि चिकित्सकों को गरीब, कमज़ोर और असाधारण जनमानों को धरातल पर करना चाहिए। नियुक्त पत्र से जिम्मेदारी शुरू होती है, लेकिन वास्तविक सफलता तब होती है जब नवनियुक्त चिकित्सक अपनी संवेदनशीलता और सेवा-भावासे लोगों का विश्वास जीता। जारखंड जैसे राज्य में, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का ढाका अब भी जीतनीयों से ज़्यादा है, ये नियुक्तियों आसा की किरण हैं। ग्रामीण और दूसरी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी से लोग वर्षों से ज़रूर रहे हैं। ऐसे में नई नियुक्तियों से नए केवल विशेषज्ञ बड़ों, बाल्कि चिकित्सा शिक्षा और उपचार की गुणवत्ता भी बहरत होगी। जरूरी यह है कि यह कदम केवल संख्या तक सीमित न रह। नियुक्त चिकित्सकों को अपने दायित्व का निर्वन्ह पूरी नियुक्ति और संवेदनाओं के साथ करना होगा। स्वास्थ्य सेवा को जनसुलभ, सस्ती और प्रभावी बनाना के लिए सरकारी उचित और चिकित्सक अपनी इच्छावित और स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त और भारोसेमंद बना सकता है।

## नजरिया

## स्टेंड की राह पर झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र

पश्चिमी सिंहगढ़ (चारखंडासा) जिले में दस नक्सलियों का स्टेंडर झारखंड पुलिस और प्रशासन की बड़ी उपरान्ति है। लंबे समय से कोलान और सारंडा क्षेत्र में सक्रिय के नक्सली होते हैं, विप्रेषेट क अधिनियम और यूपीए जैसे गंभीर लोटों में वालिंग थे। इनका आन्सर्समार्पण के केवल गुरुवार के अधिकारी से फलत है, बल्कि राज्य सरकार को आन्सर्समार्पण एवं पुनवास नीति की प्रधानविवाहों का भी प्रमाण है। डॉ.जीपी अनुराग गुप्ता ने सही कहा कि यह माजोवादी संठन के लिए बड़ा झटका है। लंगातर स्टेंडर की घटनाएं इस और झारागढ़ मुख्यधारा में ज़्यादा हो रही हैं। वर्ष 2022 से अब तक नावाचासा में 26 नक्सलियों का आन्सर्समार्पण होना इस प्रक्रिया का ठोस उदाहरण है। दूसरास, नक्सल के सामान्य के लिए गोली और बैड़क से संभव नहीं। इसके लिए विकास, संवाद और पुर्ववास तीनों का संयुक्त मिशन आवश्यक है। सरकार ने जिस प्रकार पुनवास नीति लागू की है, उसने नक्सलियों को समाज से ज़ुँड़ने का अवधारणा दिया है। साथ ही, सुरक्षा बलों के स्टार्क और बैड़क से ज़ुँड़ने का अवधारणा दिया है। अधिकारी ने जिस प्रकार करने वाले भगत अपने प्राण के जीवन से ज़ुँड़त तथ्य है कि शेष बचे राश्य का अधिकारी और अधिकारी ने ज़ो ज़ो बाल विवाह के बधान से बर्बी और शिक्षा तथा ख्वाइश का अधिकारी और अधिकारी का अवधारणा दिया है। आयोग ने न केवल आंकड़ों पर ध्यान दिया, बल्कि जारीकरता अधिनियम, हल्लालूलन, बच्चियों के लिए शिक्षा पुर्ववास और पंचायतों से साथ सम्बन्ध जैसी वालों के माध्यम से ज़मीनों पर स्थान पर, बदलाव और सुनिश्चित किया। सामाजिक संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। 2023 में भारत सरकार ने 257 ऐसे जिलों की फहचान की जहाँ

डॉ. निवेदिता शर्मा

भारत में बाल विवाह रोकने की दिशा व यूएन की रिपोर्ट

यूएन की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 4 लाख बाल विवाह रोके गए।



बाल विवाह की दर 23% से अधिक थी, इसके लिए 270 संघठनों को जिम्मेदारी दी गई और प्रत्येक संघठन को 50 गांवों में काम करने तथा कम से कम 30 लोगों को रोकने का लक्ष्य सौंपा गया। यह संख्या अकेले जूट से तो महबूब रखती ही है, साथ में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में यह निर्णायक क्षण का प्रतीक है, संयुक्त राष्ट्र महासंघियों ने एक साल पूर्व जब कहा था कि मोजदा गति से दुनिया को बाल विवाह मुक्त बनाने में लाभगत तीन साल लगायें।

अकेले कहते हैं, दुनिया के नेतृत्व वाले विवाहीयों से ज़ब रही हैं, यह किंतु विवाहीयों के बारे में होते हैं। यह विश्वितों के लिए एक तिहाई भारत में होते हैं। यह संख्या अकेले जूट से अधिक बाल विवाह रोके गए।

साल 2023-24 में ही नायर समाज, पंचायतों और कानूनी हस्तक्षेपों से 37,501 बाल विवाह रोके गए, इनमें से 59,364 मामले पंचायतों की संधियां आगामी रास्ते परिप्रेरित हैं। यह आंकड़ा प्रमाण है कि पंचायतों और स्थानीय क्षणीय होने पर सामाजिक कर्तव्यों का जड़ से उद्यापन सकती है। अपने बाल विवाह में 84% की गिरावट दर्ज की गई, वहाँ महाराष्ट्र और बिहार में यह गिरावट लाभगत 70% रही (भारत सरकार, 2024). ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन हाजारों बालिकाओं के जीवन से ज़ुँड़त तथ्य हैं जो साथ से पहले विवाह के बधान से बर्बी और शिक्षा तथा ख्वाइश का अधिकारी का अवधारणा करता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकारी सरकारी संस्थाएँ आयोग (एनसीपीसीआर) ने इस अधियान में विशेष योगदान दिया है। आयोग को रिपोर्ट के अनुसार, अपीली 27 राज्यों और 7 केंद्रायोंसित प्रदेशों में 11.5 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के उच्च जीवितमें हैं। आयोग ने न केवल आंकड़ों पर ध्यान दिया, बल्कि जारीकरता, हल्लालूलन, बच्चियों के लिए शिक्षा से ज़ुँड़त तथ्य की अधिकारी और अधिकारी का अवधारणा दिया है। राज्यों ने जिस प्रकार कानूनी प्रक्रिया आधी थीं थीं हैं। यह दर्शात है कि कानूनी प्रक्रिया आधी थीं थीं हैं। यह अकेले जूट से अधिक बाल विवाह के दिशा में यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए।

राष्ट्रीय बाल अधिकारी सरकारी संस्थाएँ और अधिकारी और अधिकारी का अवधारणा दिया है। आयोग को रिपोर्ट के अनुसार, अपीली 27 राज्यों और 7 केंद्रायोंसित प्रदेशों में 11.5 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के उच्च जीवितमें हैं। आयोग ने न केवल आंकड़ों पर ध्यान दिया, बल्कि जारीकरता, हल्लालूलन, बच्चियों के लिए शिक्षा से ज़ुँड़त तथ्य की अधिकारी और अधिकारी का अवधारणा दिया है। राज्यों ने जिस प्रकार कानूनी प्रक्रिया आधी थीं थीं हैं। यह अकेले जूट से अधिक बाल विवाह के दिशा में यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए। आयोग को रिपोर्ट के अनुसार, अपीली 27 राज्यों और 7 केंद्रायोंसित प्रदेशों में 11.5 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के उच्च जीवितमें हैं। आयोग ने न केवल आंकड़ों पर ध्यान दिया, बल्कि जारीकरता, हल्लालूलन, बच्चियों के लिए शिक्षा से ज़ुँड़त तथ्य की अधिकारी और अधिकारी का अवधारणा दिया है। राज्यों ने जिस प्रकार कानूनी प्रक्रिया आधी थीं थीं हैं। यह अकेले जूट से अधिक बाल विवाह के दिशा में यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए। आयोग को रिपोर्ट के अनुसार, अपीली 27 राज्यों और 7 केंद्रायोंसित प्रदेशों में 11.5 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के उच्च जीवितमें हैं। आयोग ने न केवल आंकड़ों पर ध्यान दिया, बल्कि जारीकरता, हल्लालूलन, बच्चियों के लिए शिक्षा से ज़ुँड़त तथ्य की अधिकारी और अधिकारी का अवधारणा दिया है। राज्यों ने जिस प्रकार कानूनी प्रक्रिया आधी थीं थीं हैं। यह अकेले जूट से अधिक बाल विवाह के दिशा में यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए। आयोग को रिपोर्ट के अनुसार, अपीली 27 राज्यों और 7 केंद्रायोंसित प्रदेशों में 11.5 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के उच्च जीवितमें हैं। आयोग ने न केवल आंकड़ों पर ध्यान दिया, बल्कि जारीकरता, हल्लालूलन, बच्चियों के लिए शिक्षा से ज़ुँड़त तथ्य की अधिकारी और अधिकारी का अवधारणा दिया है। राज्यों ने जिस प्रकार कानूनी प्रक्रिया आधी थीं थीं हैं। यह अकेले जूट से अधिक बाल विवाह के दिशा में यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए। आयोग को रिपोर्ट के अनुसार, अपीली 27 राज्यों और 7 केंद्रायोंसित प्रदेशों में 11.5 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के उच्च जीवितमें हैं। आयोग ने न केवल आंकड़ों पर ध्यान दिया, बल्कि जारीकरता, हल्लालूलन, बच्चियों के लिए शिक्षा से ज़ुँड़त तथ्य की अधिकारी और अधिकारी का अवधारणा दिया है। राज्यों ने जिस प्रकार कानूनी प्रक्रिया आधी थीं थीं हैं। यह अकेले जूट से अधिक बाल विवाह के दिशा में यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए। आयोग को रिपोर्ट के अनुसार, अपीली 27 राज्यों और 7 केंद्रायोंसित प्रदेशों में 11.5 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के उच्च जीवितमें हैं। आयोग ने न केवल आंकड़ों पर ध्यान दिया, बल्कि जारीकरता, हल्लालूलन, बच्चियों के लिए शिक्षा से ज़ुँड़त तथ्य की अधिकारी और अधिकारी का अवधारणा दिया है। राज्यों ने जिस प्रकार कानूनी प्रक्रिया आधी थीं थीं हैं। यह अकेले जूट से अधिक बाल विवाह के दिशा में यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए। आयोग को रिपोर्ट के अनुसार, अपीली 27 राज्यों और 7 केंद्रायोंसित प्रदेशों में 11.5 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के उच्च जीवितमें हैं। आयोग ने न केवल आंकड़ों पर ध्यान दिया, बल्कि जारीकरता, हल्लालूलन, बच्चियों के लिए शिक्षा से ज़ुँड़त तथ्य की अधिकारी और अधिकारी का अवधारणा दिया है। राज्यों ने जिस प्रकार कानूनी प्रक्रिया आधी थीं थीं हैं। यह अकेले जूट से अधिक बाल विवाह के दिशा में यह अपरिवर्तनीय होना चाहिए। आयोग को रिपोर्ट क







